

एक नजर
भाजपा पिछड़ों की सरकार— यदुवंश



—भारतीय बस्ती संवाददाता—
पोली (संतकरुण नगर)। मौली विकास क्षेत्र के शनिवरा बाजार स्थित राम जानकी मठ के किनारे स्थापित दुर्गा मंदिर का 2 करोड़ 79 लाख रुपये में सुदरीकरण कर पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए विधान परिषद सत्य सुभाष यदुवंश ने वैदिक मनोवा द्वारा भूमि पूजन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री यदुवंश ने कहा कि 2 करोड़ 79 हजार की लागत से मंदिर परिसर सुदरीकरण का कार्य शीघ्र शुरू होगा। साथ-साथ इस मंदिर को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सर्व समाज की सरकार है। बिना भेदभाव के सभी को प्रत्येक योजना का लाभ मिलता है। राम मंदिर के साथ साथ अन्य मंदिरों का भी जोशीयर कर पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो रहा है। राम जानकी मार्ग का चौकीकरण का कार्य भाजपा सरकार में ही संभव था। आज सरकार परिवारवाद के साथ साथ जाति धर्म कर योजना का लाभ देती थी। भाजपा सरकार पिछड़ों की सरकार है। इसी में हित है। लोचनसभा चुनाव सफाई के। तमाम करों के लोग प्रलोभन देने का काम करती लेकिन उन्हें बहकावे में न आकर फिर भाजपा सरकार बनाए।

भाजपा के जिलाध्यक्ष जगदत्ता लाल श्रीवास्तव, प्रमुख सच के जिलाध्यक्ष राम प्रताप यादव, विकास सिंह, एपीएम पदवीय देव के राजेश प्रसाद, पर्यटन अधिकारी विकास नारायण, दिगपाल पाल, बबन शर्मा, कपिल देव कर्माचार्य, पवन कर्सीन, राम अजय कर्सीन, भरत, मुयाल चौधरी, अनिल जायसवाल समेत तमाम लोग मौजूद रहे।

किशोर ने फंदा लगाकर जान दिया
—भारतीय बस्ती संवाददाता—
नगर बाजार(बस्ती)। नगर थाना क्षेत्र के ग्राम बढनी में एक 16वर्षीय किशोर ने छत के कुंडी से साड़ी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पाकर मौके पर पहुंची नगर पुलिस ने शव का पंचनामा कर परिजनों को सौंप दिया।

नगर थाना क्षेत्र के ग्राम बढनी निवासी 16वर्षीय राम शर्मा पुत्र चंद्रमन शर्मा उर्फ सिद्ध सोमवार को घर के बाहर से अचानक कहीं चला गया परिजन उस खाना देने के लिए आवाज दी। लेकिन वह नहीं मिला तभी उनकी भी बेटे को ढूँढते हुए घर में बने कमरे में गयी तो देखा कि राम का शव घर में बने छत की कुंडी से साड़ी के सहारे लटक रहा है। शव देखकर उन्होंने शोर मचाया। शोर सुनकर आसपास के तमाम लोग जमा हो गए इसी बीच सूचना पाकर मौके पर थाना प्रभारी नगर जयप्रकाश सिंह मथे फोर्स पहुंच गए परिजनों व ग्राम प्रधान के अनुरोध पर शव का पंचनामा बनकर परिजनों को सौंप दिया।

थाना प्रभारी जयप्रकाश सिंह ने बताया कि परिजनों व ग्राम प्रधान के लिखित प्रार्थना पत्र देने के बाद शव का पंचनामा कर परिजनों को सौंप दिया।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश, चुनाव से पहले स्टेट बैंक को देना होगा चंदे का हिसाब



नई दिल्ली (आभा)। चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट में और मोहलत नहीं है लेकिन थोड़ा नक दे दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एबीआई ने इस आदेश का पालन नहीं किया तो उसपर जानपुष्क अदालत के आदेश की अवहेलना का केस क्यों न चले? कोर्ट ने कहा कि एबीआई पर कंटेंट नहीं किया है लेकिन आगह किया है कि अगर उक्त आदेश का पालन नहीं हूय तो क्यों न कंटेंट चले?

चीफ जस्टिस ने कहा कि कृपा आप मुझे बताएं कि आप 26 दिनों से क्या कर रहे हैं? इसके बाद जस्टिस खन्ना ने कहा कि आप कुछ स्वीकार

कर रहे हैं कि डिटेल् देने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो इन 26 दिनों में तो काफ़ी काम हो सकता था। कोर्ट ने एबीआई से कहा कि चुनावी बॉन्ड की जानकारी तुरंत चुनाव आयोग को दे। चीफ जस्टिस चंद्रचूड ने एबीआई को आदेश दिया कि चुनाव आयोग को इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध कराए। इसमें राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी बॉन्ड को भुनाने की जानकारी भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों के दौरान एबीआई से पूछा कि अभी तक

निःशुल्क चिकित्सा शिविर में 156 का उपचार



—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। सोमवार को मेदाता हॉस्पिटल लखनऊ एच रोटी क्लब बस्ती सेंट्रल द्वारा निष्पक्ष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन अन्पूर्णा रसोई पुरानी बस्ती के प्रांगण में किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ अन्पूर्णा रसोई के प्रबंधक रामाजसोदी एवं पत्रकार प्रमोद मिश्र वृद्ध द्वारा किया गया। उपस्थित अवसर पर रोटी क्लब बस्ती सेंट्रल के अध्यक्ष अश्वथ अम्बुवाल एवं सचिव एच. के. पाण्डेय ने स्वास्थ्य शिविर के बारे में लोगों से चर्चा कर बताया कि आम जनमानस को मेदाता जैसे बेहतर चिकित्सा संस्थान के विशेषज्ञों द्वारा बेहतर चिकित्सा सुविधा का लाभ बस्ती संसाजक रोटेशन वामिक मेराज, आदर्श अग्रवाल, विमल कुमार गुरुनगर के साथ ही अनेक लोग उपस्थित रहे।

नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए लागू

नई दिल्ली (आभा)। देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के नियम लागू हो गए हैं। केंद्र सरकार ने सोमवार शाम को नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर अहमदाबाद जारी कर दी है। इसके लिए पौडेल भी तैयार कर लिया गया है, जिसके जरिए हर मुस्लिम प्रवासी मुसलमान को लोग नागरिकता पाने के लिए अनिवार्य कर सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। कुछ दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्रालय को नागरिकता संशोधन के कैंडा करने के लेकर जानकारी दे दी है। आपके पास पहले से डिटेल् मौजूद है।



अधिनियम, 2019 के नियमों को तैयार करने के लिए लोकसभा में अधीनस्थ कानून पर संसदीय समिति की तरफ से एक और विस्तार मिला था। पहले के संसा विस्तार की अवधि भी जनसरी को खत्म हो गई थी। सीएए के नियम

बिजली कर्मचारी संघ ने सौंपा 19 सूत्रीय ज्ञापन: समस्याओं के निस्तारण की मांग

—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। सोमवार को तरहर प्रगति बिजली कर्मचारी संघ के क्षेत्रीय अध्यक्ष अशर्फीलाल के नेतृत्व में संस पदाधिकारियों ने अधीनस्थ अभिनियम विद्युत वितरण मण्डल में राम बुझार के माध्यम से अध्यक्ष उ.प्र. पावर कारपोरेशन लिमिटेड को समस्याओं के निस्तारण और समझौते को पालन हेतु 19 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा।



—नियमित किये जाय संविदाकर्मी— अशर्फीलाल

भोजे ज्ञापन में संविदा कर्मचारियों को दलंगन, उद्दिष्टा सरकार की तरफ नियमित किये जाने, जब तक नियमित नहीं किया जाता 28 हजार रुपया मानव्य देते जाने, दुर्घटना की स्थिति में मुकदमे इलाज की सुविधा उपलब्ध कराते जाने, पुरानी भवन व्यवस्था बहाल किये जाने, पदोन्नति का समबद्ध वेतनमान दिये जाने, टी.डी. 2 से जेई के प्रमेन्ति का कोटा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत किये जाने, ज्ञान लिफिक का भी भाति पदोन्नति किये जाने, मजदूरी में नियमानुसार तेनाति, कार्यकारी नवायन के की वरिध काकांकी के रिक्त पदों पर पदोन्नति किये जाने, तृतीय और चतुर्थ अंति कर्मचारियों को अवर अभिनयती की भाति 4200 एवं 2600 रुपया से दिये जाने, उपरान्त नियम की पक्षियोजनाओं पर चिकित्सापत्र में विशेषज्ञ चिकित्सकों

प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ के क्षेत्रीय अध्यक्ष अशर्फीलाल ने कहा कि बिजली कर्मचारी संघ की प्रांतीय कमेटी द्वारा समय-समय पर कर्मचारी समस्याओं के समाधान हेतु एजेंडे दिये जाने, परतु समस्याओं का समाधान आज तक न होने के कारण लोगों में रोष है। समस्याओं का प्रमादी समाधान न हुआ तो संघ आन्दोलन को बाध्य होगा। ज्ञापन सौंपने वालों में मुख्य रूप से सूर्य प्रकाश, अनिल कुमार, मसूद आलम, दिनेश कुमार, राजेश त्रिपाठी, निर्मला देवी के साथ ही संघ के अनेक पदाधिकारी शामिल रहे।

आचार्य संहिता की आड़ में न तोड़ी जाय वैध होर्डिंग, सौंपा ज्ञापन

—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। नगर पालिका परिषद द्वारा अभिनियम चलाकर निम्नानुसार निर्धारित शुल्क जमा करने के बावजूद कैव होर्डिंगों को तोड़कर उठा ले जाने से एडवर्टाइजिंग एगोसिएशन पदाधिकारियों में रोष है। सोमवार को एगोसिएशन अध्यक्ष नोमान अहमद के साथ बस्ती उद्योग व्यापार प्रतिनिधि। मण्डल अध्यक्ष आनन्द राजपाल, महामंत्री सूर्य कुमार बुलन ने जिलाधिकारी को सम्बोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा।



ज्ञापन देने के बाद आनन्द राजपाल ने कहा कि निम्नानुसार कैव होर्डिंगों को हटाय जाना पूरी तरह से गलत है। नोमान अहमद ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के बन्धान देश के बावजूद नगर पालिका कर्मियों द्वारा उद्योगिकारियों की होल्डिंगों को तोड़कर उठा ले जाने से एडवर्टाइजिंग एगोसिएशन पदाधिकारियों में रोष है। इस लामन्य में उद्योगिकारियों की उधुगी सपने डूबे हैं। कहा कि निम्नानुसार सौंपे गये होर्डिंगों को तोड़ा जाना निहित विरुद्ध है। यह विनाजुन है कि कि निम्नानुसार सौंपे गये होर्डिंगों को

तोड़या देगा, इसके होर्डिंग क्षेत्र में काम करने वालों को काफी नुकसान होगा, ऐसा कदापि न किया जाना। ज्ञापन सौंपने वालों में मुख्य रूप से प्रभात सोनी, शेष नरवान गुप्ता, फरमान अहमद, शांति भगत कुमार, हबीब, राम दयाल, मनीष श्रीवास्तव, मसूद यादव, अरुण पाण्डेय, उदयनगर मसूद, फुरकान अहमद, आताक प्रमोद, इरशाद खान, मोनिस खान आदि शामिल रहे।

दलित के अपहरण, हत्या मामले में बहुजन मुक्ति पार्टी ने सौंपा ज्ञापन:दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग

—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। सोमवार को बहुजन मुक्ति पार्टी जिलाध्यक्ष बुद्धरा ने नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारियों, जिलाधिकारी के एक प्रतिनिधि मण्डल ने जिलाधिकारी को सम्बोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। मान किया कि परसुरामपुर थाना क्षेत्र के रोहदा गांव में दलित राजाजान के अपहरण और हत्या मामले में पुलिसकर्मी सुरेन्द्र कुमार वर्मा के विरुद्ध भी मुकदमा दर्ज कर न्याय दिलाया जाए। पुलिस मामले में पोलियोटी कर हत्या के मामले में दुर्घटना में बदलकर रफा दफा कर देना चाहती है। बताया कि दलित आनीता देवी अपनी गुलाब चन्द ने पुलिस अधीक्षक को जस्टिस्ट पर भोजन करने सरसुर राजाजान के अपहरण और हत्या मामले में पुलिसकर्मी सुरेन्द्र कुमार वर्मा के विरुद्ध भी मुकदमा दर्ज करने की



मांग किया था किन्तु कोई कार्रवाई नहीं हुई। यदि पुलिसकर्मी सुरेन्द्र कुमार वर्मा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर निरपराधी को गैर हो तो बहुजन मुक्ति पार्टी आन्दोलन को संचाल होगी। ज्ञापन देने के बाद बुद्धरा राना ने बताया कि परसुरामपुर पुलिस

कवियों, शायरों ने दिया संदेश ‘एक बार और जाल डाल रे मछरे, जाने किस मछली में बन्धन की चाह हो’



—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। वरिष्ठ कवि एवं लोक गिय बासनी के साथ ही 7 पुरातकों के रचयिता डॉ. रामकृष्ण लाल ‘जगमग’ की आठवीं कृति ‘बाल चेतना’ का लोकार्पण प. अटल बिहारी वाजपेयी प्रेक्षागृह में किया गया। इस अवसर पर अनुसूच लक्ष्य और तय्य सुमन द्वारा विद्युत अधिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें देश के ख्यातिविश्व कवियों, शायरों ने हिस्सा लिया। देर रात तक चले अतिथि उप जिलाधिकारी सदर शुरुयण गण्डक के कवि समाज निगमन में साहित्यकारों की भूमिका महत्वपूर्ण है। कहा कि बाल कविता लिखना सबसे कठिन कार्य है। इसमें कवि को बालक बनना पड़ता है। महाकवि सूरदास की परम्परा किंकर्तव्य पूर्वक अनुभव आवाक को चरितार्थ करके इसे डॉ. रामकृष्ण लाल ‘जगमग’ की आठवीं कृति ‘बाल चेतना’ निर्विवाद रूप से पाठकों में लोकप्रिय होगी। अज्ञात करते हुए डॉ. रामकृष्ण लाल ‘जगमग’ ने कहा कि डॉ. रामकृष्ण लाल ‘जगमग’ ने सौंदर्य के साथ ही हास्य व्यंग्य के साथ ही गंभीर रचनाओं के द्वारा



—डॉ. रामकृष्ण लाल ‘जगमग’ कृत ‘बाल चेतना’ का लोकार्पण
साहित्य को समृद्ध कर बाल रचना कर उन्होंने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध किया है। ‘बाल चेतना’ के लोकार्पण के बाद कवि सम्मेलन का आरम्भ प्रिन्स गीतकार डा. बुद्धिनाथ मिश्र द्वारा प्रस्तुत सरस्वती वंदना से हुआ। उपस्थित गीत ‘एक बार और जाल डाल रे मछरे, जाने किस मछली में बन्धन की चाह हो’ से प्रेक्षागृह तालियों से गूँज उठा। डा. सुरेश गौतम की रचना ‘पूरुखों ने जो निर्वासन में राखि, त्यग की वो कर्माई बने चाहिये, राम वर-चर में हो प्रमोद है नगर, एक मस्त जैसा भाई हमें चाहिये’ ने कवि सम्मेलन को नई ऊँचाई दी। कवि सम्मेलन का संचालन करने वाले हास्य व्यंग्य के प्रसिद्ध कवि सहस्र अस्थाना ने कुछ पुरे कहकर कवि गिरिगौरी की, नेता से तुलना करमा मनापाप है सौंदर्य किन बदलने में मान में नेता गिरिगौरी का बाप है। शांलाल गौरी की रचना ‘खाल तो चलते हैं पद के पीछे खेत सन्धी,

गुनाह हवा के हैं, मुजरिम चरगम होते हैं’ सुनकर वातावरण को गंभीर बना दिया। डा. ज्ञानेन्द्र द्विवेदी दीपक ने कुछ यूँ कहा ‘बजाता है सरगम की धुन पर करवना, है दस वर्ष का बाबुरी बेवता है। ओज के सारवत हलतार प्रोफेसर ओम पाल सिंह निडर की पंक्तियाँ ‘यही बापजू है मेरी कविता गणी से कि सब कुछ बिके पर कसम किया है न जाने के द्वारा संदेश दिया। महेश प्रताप श्रीवास्तव की पंक्तियाँ ‘जो घर पर पीते हैं बिना पीने की चाय, महफिल में वहीं रसगुल्ला खोजते हैं’ सुनकर सुमन के रंगीनो पर कटाक्ष किया। कवियत्री डा. अजना ने बजाता और ओज के अरक रचनाओं से कवि सम्मेलन को संतुष्ट किया। डा. रामकृष्ण लाल ‘जगमग’ ने काली माता आन मौका दे तो उत्सवकर देख लो, मौन इतने में नाहीं है, तेरे बब खाने में हैं’ सुनकर बहानी बूझी। डॉ. विनोद उपाध्याय के शेर ‘सुनुल स जितम था या कोई महाबाव था, मखमल की सेज पर कपूर वातावरण को गंभीर बना दिया। डा. ज्ञानेन्द्र द्विवेदी दीपक ने कुछ यूँ कहा ‘बजाता है सरगम की धुन पर करवना, है दस वर्ष का बाबुरी बेवता है। ओज के सारवत हलतार प्रोफेसर ओम पाल सिंह निडर की पंक्तियाँ ‘यही बापजू है मेरी कविता गणी से कि सब कुछ बिके पर कसम किया है न जाने के द्वारा संदेश दिया। महेश प्रताप श्रीवास्तव की पंक्तियाँ ‘जो घर पर पीते हैं बिना पीने की चाय, महफिल में वहीं रसगुल्ला खोजते हैं’ सुनकर सुमन के रंगीनो पर कटाक्ष किया। कवियत्री डा. अजना ने बजाता और ओज के अरक रचनाओं से कवि सम्मेलन को संतुष्ट किया। डा. रामकृष्ण लाल ‘जगमग’ ने काली माता आन मौका दे तो उत्सवकर देख लो, मौन इतने में नाहीं है, तेरे बब खाने में हैं’ सुनकर बहानी बूझी। डॉ. विनोद उपाध्याय के शेर ‘सुनुल स जितम था या कोई महाबाव था, मखमल की सेज

"मुझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"—वेडेल फिलिप्पा

दैनिक

भारतीय बस्ती

बस्ती 12 मार्च 2024 मंगलवार

सम्पादकीय

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

अक्सर सुनने में आता है कि विचारों की अभिव्यक्ति को लेकर पुलिस का रवैया आक्रामक होता है और वह अनावश्यक धाराओं में व्यक्ति को गिरफ्तार व प्रताड़ित करने में जल्दबाजी दिखाती है। ऐसे ही एक प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को राज्य के किसी फैसले पर आलोचना करने का अधिकार है। दरअसल, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की निंदा करने वाली एक टिप्पणी पर एक प्रोफेसर के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करते हुए शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी की। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र पुलिस ने 'पांच अगस्त को ब्लैक डे जम्मू और कश्मीर' और '14 अगस्त पर पाकिस्तान को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं' जैसे व्हाट्सएप संदेश पोस्ट करने के लिये प्रोफेसर जावेद अहमद पर आईपीसी की धारा 153-ए के तहत मामला दर्ज किया था। दरअसल, यह मामला धर्म, जाति आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने पर दर्ज किया जाता है। इसी वजह से बॉम्बे हाईकोर्ट के एक आदेश को रद्द करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि राज्य के कार्यों की हर आलोचना या विरोध को धारा 153-ए के तहत अपराध माना जाता है तो यह संविधान प्रदत्त अनिवार्य कर्तव्य के विरुद्ध, लोकतंत्र की आत्मा के हनन जैसा होगा। इस मामले पर चर्चा करते हुए शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि वैध तरीके से असहमति का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)ए के तहत गारंटीयुद्ध अधिकार है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक सिद्धांत है जो प्रतिशोध, संसरण या कानूनी मंजूरी के डर के बिना किसी व्यक्ति या समुदाय को अपनी राय और विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा और अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को मानव अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। कई देशों में संवैधानिक कानून हैं जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। बोलने की आजादी और अभिव्यक्ति की आजादी जैसे शब्दों का इस्तेमाल राजनीतिक चर्चा में एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। हालाँकि, कानूनी अर्थ में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में उपयोग किए गए माध्यम की परवाह किए बिना, जानकारी या विचार प्रसार करने, प्राप्त करने और प्रदान करने की कोई भी गतिविधि शामिल है।

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल दिसंबर में अनुच्छेद 370 को केंद्र सरकार द्वारा निरस्त करने के वर्ष 2019 के फैसले को बरकरार रखा था। इसके बावजूद केंद्र सरकार के फैसले को लेकर अस्थिरता की आवाजें अभी कम नहीं हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में पिछले दिनों प्रधानमंत्री की जम्मू-कश्मीर यात्रा के दौरान भी विपक्षी नेताओं की ऐसी प्रतिक्रिया देखी गई। लेकिन प्रोफेसर के मामले में पुलिस की विवादास्पद भूमिका को न्यायिक और सार्वजनिक जांच के दायरे में ला दिया है। दरअसल, देखा जाता है कि ऐसे मामलों में पुलिस आनन-फानन में असहमति जताने वाले को पकड़ने के लिये मामले को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर देती है। यही वजह है कि अदालत को चक्का पड़ा कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अवधारणा तथा इस आजादी को लेकर उचित संयम की सीमा के बारे में हमारे पुलिस तंत्र को जागरूक व शिक्षित करने की जरूरत है।

निश्चित रूप से देश के नीति-नियंत्रणों को शीर्ष अदालत के सुझाव पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। वहीं देश के पुलिसकर्मियों को संविधान में निहित लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। निस्संदेह, सामान्य मामलों के आधार पर मुकदमें दर्ज करना पुलिस के निरंकुश व्यवहार को ही दर्शाता है। जो जांच के लिए संपन्न है एक अलोकतांत्रिक कदम कहा जाएगा। विचारों पर सजा चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में अब पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर व्यक्ति विशेष को असामाजिक व राष्ट्रविरोधी करार देने से रोका जाएगा। निस्संदेह, हिंसा व घृणा को बढ़ावा न देने वाली टिप्पणियों पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।

एकला चलो की डगर पर बसपा का हाथी



—आशीष वशिष्ठ—

बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने फिर एक बार आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर घोषणा की है कि बहुजन समाज पार्टी अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी। मायावती इसके पहले भी कई बार लोकसभा चुनाव के लिए किसी भी तरह के गठबंधन में शामिल होने से इनकार करती रही हैं। उन्होंने चुनाव के लिए अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा भी नहीं की है जिसके कारण उनके इंडिया गठबंधन में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। 2024 के आम चुनाव में राजनीतिक लिहाज से उत्तर प्रदेश जैसे अहम राज्य में हर राजनीतिक दल अधिक से अधिक सीटें हासिल करना चाहता है। इसलिए एनडीए और इंडिया गठबंधन में छोटे-बड़े दल शामिल होकर अपना राजनीतिक कद और हैसियत बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे में मायावती का किसी गठबंधन का हिस्सा न बनना कई प्रश्न खड़े करता है। प्रश्न यह है कि क्या अकेले चुनाव लड़कर मायावती एनडीए और इंडिया गठबंधन को चुनौती दे पाएंगी? क्या मायावती को भरोसा है कि उनका कोई वोट बैंक पूरी तरह उनका साथ देगा? क्या मायावती को लगता है कि किशोरीय मुकबले में बसपा हवी रहेगी? क्या मायावती को इस बात



का भरोसा है कि इंडिया गठबंधन की बज्जु मुस्लिम मतदाता उनके साथ मिलाई से खड़े होंगे? क्या मायावती चुनाव नतीजों के हिसाब से रणनीति का खुलासा करेंगी? क्या मायावती एकला चलो की राह पर हैं या फिर वो जिस तरह से खामोश हैं उसके पीछे कोई बड़ा प्लान है? बसपा प्रमुख ने पिछले छह-सात महीने में अकेले चुनाव लड़ने की बात कई बार कही है, साथ ही यह भी कहा कि गठबंधन करने से उनको नुकसान होता है। इसमें कोई गलत बात नहीं है कि कोई पार्टी गठबंधन नहीं करे और चुनाव अकेले लड़े। लेकिन पार्टी लड़ने हुए तो दिखाई दें। मायावती की बहुजन समाज पार्टी बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के साथ गठबंधन कर चुकी है। लेकिन बीजेपी हाई दरवाजों के बसपा का भाजपा के बीजेपी के प्रति व्यादा रुझान देखा गया है। मायावती तीन बार भाजपा के सहयोग से यूपी की मुख्यमंत्री भी बन चुकी हैं।

बसपा ने पिछला लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिल कर लगा था लेकिन मायावती का सहभाग्य से प्रत्येक से 10 सीट पर पहुंचने के

बाद ही उन्होंने तालमेल समापत कर दिया था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बसपा का वोट बैंक भी खिसक रहा है। बसपा सुप्रीमो भले ही ये कहें कि गठबंधन से उनकी पार्टी को नुकसान होता है लेकिन सच्चाई तो ये है कि पिछले लोकसभा चुनाव में गठबंधन का ससेरे ज्यादा लाभ बसपा को ही हुआ था। वर्ष 1996 में बसपा 6 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल कर मिला था। वर्ष 1998 में बसपा को 20.6 प्रतिशत मत मिले थे। वर्ष 1998 में बसपा को बार सीटें मिली और वोट प्रतिशत बढ़कर 20.9 प्रतिशत हो गया। वर्ष 1999 में बसपा को 14 सीटें मिली और मत 22.08 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2004 में सीटें बढ़कर 19 हो गईं और 24.67 प्रतिशत मत मिले। बसपा ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वर्ष 2009 में किया जब पार्टी को 20 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हुई और 27.42 प्रतिशत मत मिले।

बसपा की स्थिति साल 2014 से बदलती चली गई। बीस सांसदों वाली बसपा को इस चुनाव में एक भी सीट हासिल नहीं हो पाई और उसका मत प्रतिशत भी गिरकर 19.77 प्रतिशत पर आ गया। बसपा के वोट में लगभग आधे प्रतिशत की

गिरावट आई। 1996 के बाद बसपा का ये सबसे बुरा प्रदर्शन था। वर्ष 2019 में बसपा ने सपा के साथ गठबंधन किया। जिसका बसपा को भरपूर लाभ हुआ और पार्टी शून्य सीटें वाली बसपा ने दस सीटों पर विजय प्राप्त की। जबकि उसका मत और कम हुआ। इस चुनाव में बसपा को सपा के साथ गठबंधन कर 19.43 प्रतिशत ही मत मिले। विधानसभा में बसपा का केवल एक विधायक है।

एक वो समय था जब बसपा चुनाव से काफी समय पहले ही उम्मीदवार घोषित कर देती थी। सबसे पहले संभवतः बसपा ने ही चुनाव से महीने पहले उम्मीदवार घोषित करने शुरू किए थे। लेकिन अब चुनाव बिल्कुल सिर पर आ चुके हैं। और बसपा उम्मीदवारों की घोषणा की बजाय अकेले चुनाव लड़ने का पुनरा रिकार्ड बनाए जा रही है। जबकि भाजपा, सपा, राबोद और सुभाषा कई सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं। बड़ी मशक्कत के बाद बीते 10 मार्च को बसपा ने यूपी की मुगदाबाद सीट से मो. इरफान सैफी को अपना पहला प्रत्याशी घोषित

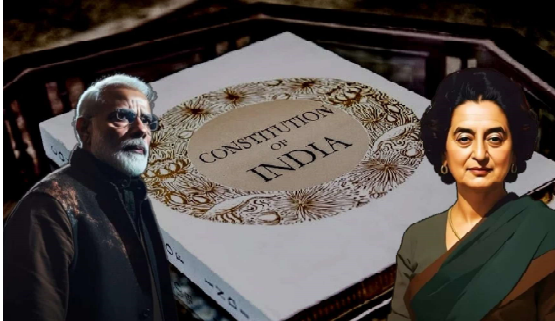
किया है। पिछले एक दशक में मायावती के कई भरोसेमंद सिपहसालार दूसरी पार्टियों में शामिल होते चले गए। बीते चुनाव में जीते 10 सांसद भी नई सिपाही संभालना तलाश रहे हैं। इसमें अंबेडकर नगर से सांसद रीतेश पांडे बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उन्हें बीजेपी ने टिकट भी दे दिया है। वहीं गाजीपुर सांसद अफजल अंसारी को सपा उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। वहीं अमरौहा से दानिश अली अब कांग्रेस के खेमे में हैं। जौनपुर से सांसद श्याम सिंह यादव भी कांग्रेस की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। बिजनौर से सांसद मनुकु नागर, लालगंज लोकसभा सीट से सांसद संगीता आजाद के भी पाला बदलने के कयास लगाए जा रहे हैं। यूपी समेत देश के अन्य राज्यों में बीएसपी का सिपाही ग्राफ चुनाव पर चुनाव गिरता ही जा रहा है। पिछले वर्ष विधानसभा चुनावों में आकाश आनंद छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में पार्टी का चुनावी अभियान संचालन रहे थे, जहां पार्टी पिछले चुनाव की तुलना में काफी खराब प्रदर्शन की है। राजस्थान छोड़कर किसी भी राज्य में बसपा का खाता तक नहीं खुला और वोट फीसदी में भी गिरावट आई। बसपा अब उत्तर प्रदेश और बाहर के राज्यों में हर जगह कमजोर दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली समेत उत्तर भारत के राज्यों में पार्टी संभवतः लचर हाल में है। पार्टी अपने कोरे दलित वोटरों को भी पकड़कर नहीं सफल नहीं हो पाई है। सत्ता से बाहर होने के बाद मायावती से दलितों का मोहभंग लगातार होता जा रहा है। वास्तव में, कांशीराम ने बसपा का ही सिपाही समीकरण बनाया था, वो गबड़बाद युवा था और दलितों के बीच चंद्रशेखर आजाद नई लीडरशिप के रूप में खुद को खड़े

कर रहे हैं। इस तरह से बीएसपी सिपाही चक्रव्यूह में घिरी हुई है, जहां एक तरफ बीजेपी गैर-जायद वोटों को अपने पास में ले चुकी है तो जायद वोट को चंद्रशेखर अपने साथ जोड़ने में लगे हैं। दलित राजनीति का चेहरा माने जाने वाली मायावती की चमक अब पहले जैसी नहीं रहे हैं। वर्ष 2009 में 27.42 प्रतिशत मत वाली बसपा 2019 के आम चुनाव में 19.43 प्रतिशत पर आ गई। जबकि इस चुनाव में बसपा सपा के साथ गठबंधन में थी। 2007 में बीएसपी यूपी में भले ही पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में सफल रही हो, लेकिन उसके बाद से ही निरावद देखने को मिल रही है। 2012 के यूपी चुनाव में बीएसपी 2007 के 206 सीट से घटकर 80 सीटों पर आ गई। 2017 में बीएसपी महज 19 सीटों पर सिमट गई। 2022 के चुनाव में बीएसपी एक सीट जीतने के साथ 13 फीसदी वोट पर सिमट गई। प्रदेश में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही बसपा को अपनी सुभोगी और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के गृह जन्मपट्ट में भी लोकसभा चुनाव लड़ने की जिद चेहरों का अकाल पड़ गया है। चुनाव सिर पर है, बावजूद इसके बसपा के खेमे में कोई खास हलचल दिखाई नहीं देती। मायावती और बसपा के किसी दूसरे नेता अभी तक कोई चुनावी रणनीति भी नहीं की है। 2024 के आम चुनाव में बसपा का वोट प्रतिशत और सांसदों की संख्या नहीं बढ़ती है तो पार्टी के लिए सिपाही राह मुश्किल हो जाएगी। 2014 में अकेले लड़ने का खामियाख बसपा मुगुल चुकी है। किसी मानवीय ने बसपा के लिए चुनाव का रास्ता मुश्किलों में डाला है। उत्तर प्रदेश की सत्ता पर भार बाढ़ काबिज होने वाली मायावती का अकेले चुनाव लड़ने का निष्कर्ष उभरते हुए घातक सिद्ध हो सकता है।

क्या भाजपा बदल पायेगी संविधान

—अभिनव आकाश—

हम सब भारत के संविधान की कसमें तो खूब खाते हैं या लोगों को खसते हुए सुनते हैं। पर क्या अपने संविधान देखा है? अगर कोई फोटो वहीरह में देखा भी हो तो एक चीज तो आपको पता ही होगी की अपना संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। सोने पर सुहावा ये कि पूरा संविधान हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया। हाथों से कंरीया किया गया, न कोई प्रिंटिंग हुई और न कोई टाइपिंग। इस संविधान के पहले पन्ने पर संविधान की आत्मा है। यानी संविधान की प्रस्तावना। वहीं प्रस्तावना को हम भारत के लोग से सुनो रही है। लेकिन इन दिनों बीजेपी के एक सांसद के बयान के बाद संविधान में बदलाव को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। कर्नाटक से बीजेपी सांसद अनंत कुमार हेमड़े ने जनसभा में कहा कि संविधान में संशोधन के लिए और कांग्रेस की ओर से इसमें जोड़ी गई अनावश्यक चीजें हटाने के लिए बीजेपी को संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होगी। आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए को 400 बार सीटें मिलने पर राज्यसभा में बहुमत हासिल करने में मदद मिलेगी। हेमड़े के बयान पर राजनीति तेज हो गई है। हेमड़े के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस ने आरोप लगाया कि संविधान को शक्ति से लिखना और रच कर मायावती बीजेपी और आरएसएस का अजंदा है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सांसद का बयान कि उन्हें 400 सीटें संविधान बदलने के लिए चाहिए, नरेंद्र मोदी और उनके सघ परिवार के पिछे मुँहों का सार्वजनिक एलान है। कर्नाटक के सांसद की टिप्पणी को लेकर बिजपा की ओर से सत्तारूढ़ दल पर निशाना साधने के बीच पार्टी प्रवक्ता गोवर्धन नाटिया ने रिप्लेट किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमेशा संवैधानिक लोकाचार और राष्ट्रीय हित के अनुरूप काम किया है। हालांकि, आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि संविधान में इससे पहले संशोधन या बदलाव नहीं किए गए हैं। जून 1951 में संविधान में पहला संशोधन हुआ। उसके बाद ये सिलसिला लगातार चलता रहा है। कुल संशोधनों का औसत निकाल



जाए तो हर साल लोक दो संशोधन होते हैं। एक वक्त में तो इंदिरा गांधी ने एक संशोधन के जरिए गांधी ने एक ही पार्टी किसी भी कौम पर त्यागपत्र देने को राजी नहीं हुई। परिणामस्वरूप, 25 जून, 1975 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के त्यागपत्र न देने तक देशभर में धरना-दर्शन करने की घोषणा कर दी। अपने विरुद्ध आलोचकों को देखते हुए कुर्सी के मोह में अंधे ही हो चुकी इंदिरा गांधी ने ऐसा कदम उठाया, जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की हो। 25-26 जून, 1975 की दरम्यानी रात को इंदिरा गांधी ने देश को आपातकाल के मुँह में धकेल दिया। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के शासन के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली ने संविधान की धारा-352 के अधिन में आपातकाल की घोषणा कर दी। आपातकाल में सबसे पहले भारतीय संविधान का 38वां संशोधन 22 जुलाई 1975 को पास हुआ। इस संशोधन के अनुसार न्यायपालिका से आपातकाल की न्यायिक समीक्षा का अधिकार छीन लिया गया। करीबन बीस बार इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनने पर इंदिरा गांधी को प्रत्यक्ष रूप से इंदिरा गांधी के लिए संविधान का 39वां संशोधन लगाया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा का चुनाव रद्द कर दिया। लेकिन इस संशोधन ने कोर्ट से प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति के बयान की जांच के अधिकार को ही छीन लिया। 40वें और 41वें संशोधन के जरिए संविधान के कई प्राधान्यों को बदलने के बाद 42वां संशोधन पास किया गया। इंदिरा गांधी ने 'गरीबी हटाओ

गांधी से प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने की मांग उठाने लगी थी। लेकिन श्रीमती गांधी किसी भी कौम पर त्यागपत्र देने को राजी नहीं हुई। परिणामस्वरूप, 25 जून, 1975 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के त्यागपत्र न देने तक देशभर में धरना-दर्शन करने की घोषणा कर दी। अपने विरुद्ध आलोचकों को देखते हुए कुर्सी के मोह में अंधे ही हो चुकी इंदिरा गांधी ने ऐसा कदम उठाया, जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की हो। 25-26 जून, 1975 की दरम्यानी रात को इंदिरा गांधी ने देश को आपातकाल के मुँह में धकेल दिया। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के शासन के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली ने संविधान की धारा-352 के अधिन में आपातकाल की घोषणा कर दी। आपातकाल में सबसे पहले भारतीय संविधान का 38वां संशोधन 22 जुलाई 1975 को पास हुआ। इस संशोधन के अनुसार न्यायपालिका से आपातकाल की न्यायिक समीक्षा का अधिकार छीन लिया गया। करीबन बीस बार इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनने पर इंदिरा गांधी को प्रत्यक्ष रूप से इंदिरा गांधी के लिए संविधान का 39वां संशोधन लगाया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा का चुनाव रद्द कर दिया। लेकिन इस संशोधन ने कोर्ट से प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति के बयान की जांच के अधिकार को ही छीन लिया। 40वें और 41वें संशोधन के जरिए संविधान के कई प्राधान्यों को बदलने के बाद 42वां संशोधन पास किया गया। इंदिरा गांधी ने 'गरीबी हटाओ

जैसे नारों के साथ एक समाजवादी और गरीब-समर्थक छवि के आधार पर जनता के बीच अपनी सीधेकी को मजबूत करने का प्रयास किया था। लेकिन गौर करने वाली बात है कि संविधान में 42वां संशोधन, 1976 में पारित हुआ जब आपातकाल लागू था। इस दौरान संग्रभू लोकतांत्रिक गृहाराज्य' शब्दों को संग्रभू समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गृहाराज्य' से बदल दिया गया। इस दौरान राष्ट्र की एकता शब्द को 'राष्ट्र की एकता और अखंडता' में भी बदल दिया। 42वें संशोधन में कई अन्य प्रवधान थे, जिसके द्वारा इंदिरा सरकार ने सत्ता को और केंद्रीकृत करने की कोशिश की थी। हालांकि इनमें से कुछ को आपातकाल के बाद सत्ता में आई जनता सरकार ने 44वें संविधान संशोधन के जरिए रद्द कर दिया। संविधान की प्रस्तावना में हुए बदलाव से छेड़छाड़ नहीं की गई।

अनुच्छेद 368(2) के तहत संसद 'प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत से और उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से एक विधेयक पारित करने के संविधान में संशोधन कर सकती है। उसके बाद, विधेयक राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाएगा जो अपनी सभमति देता और उसके बाद संविधान में संशोधन किया जाएगा। संविधान संशोधन विधेयकों के लिए संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया लागू नहीं होती है। अगस्त 2023 तक देश के संविधान में 127 संशोधन हो चुके हैं।

लोकतंत्र में अमर्यादित भाषा



—मधुरेन्द्र सिन्हा—

भारतीय राजनीति जिस मोड़ से गुजर रही है उसमें कीचड़ ज्यादा है और तथ्य कम हैं। हर तरफ से हर रोज कुछ न कुछ अंगरंग प्रयास और सरसी बातों के अलावा किसी राजनेता पर छीटाकशी आम बात हो गई है। कुठित लोग जिनमें राजनीतिक नेता बड़े पैमाने पर हैं, किसी के भी बारे में अग्रदूत भाषा का इस्तेमाल करते हैं नहीं चुकी। बहुत से तो इसमें अपनी शान समझते हैं और अपने को बड़ा समझने लगते हैं। कुछ तो जानबूझकर ऐसा करते और करते हैं ताकि मुक्त में पकड़लौती मिले। कई तो संसद और विधानसभाओं में भी अपनी कच्ची जुबान का इस्तेमाल करते हैं।

भारतीय राजनीति में हल्की और सरसी बातें कहने का चयन काफी सख्त है। लेकिन पिछले दो दशकों में यह विलक्षण सा धारण कर चुका है। उदास सुनब राम मोहंनर लोहिया ने इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहा था तो काफी विवाद हुआ और बीजेपी विधान में लोगों ने साक्षी का विरोध किया। दरअसल, कांग्रेस में बड़े पर रहने के बाद जब वह अलग हुए तो राजनीति में उनकी यह कौशल नहीं रही थी। यह कारण व कुठित होने लगे और यह कुछ उनसे व्यवहार और उनके बोल में साफ झलकने लगी।

यही भाव आज के उन ज्यादातर राजनीतिज्ञों में दिखाता है जो बहुत में जी रहे हैं। ऐसे ही नेता अपराधों का इस्तेमाल करते हैं। सत्ता से विध्वंस रहना या फिर उसे पाने के लिए किसी भी सोमा तक बलें जाला, व्यामोहक और धमकाने में भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। यह बहुत तो सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी बोलते हैं और जब विवेक संचालन होता है तो दूसरों के लिए अपराधों का इस्तेमाल करते हैं। यह बहुत तेजा अपने सलाहकारों की बातों पर चढ़ते हुए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इतना सख्त बड़ा उदाहरण हमें सचिंद्र भुवनेश्वर या जिन्होंने पुरातन में भाषण देते बड़े मर्दात लंड ही और तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में मंच से कहा-मौत के सौदागर।

इस अपराध से ऐसे शीर्ष नेताओं की छति को ही नुकसान हुआ न कि नरेंद्र मोदी को। सभी तरह उनकी आलोचना हुई लेकिन ऐसे नेता बांधे जा सकते हैं और बांधे जा सकते हैं। इनके शब्दों का असर के लिए नहीं बढ़ता। इनके शब्दों का असर के लिए नहीं बढ़ता। पिछले दिनों तो उन्होंने कहा जब भीमान कभी और भुले मत। यह उनके अतीव की खोश को दिखाता है। अभी चुनाव में थोड़ा सत्ता के तो आने वाले समय में क्या-क्या बयानवाजी होती है, कतना मुश्किल है क्योंकि इन दिनों उनके सलाहकार हैं बहलले जयपरास राम जो खुद भी अक्सर हल्की भाषा का इस्तेमाल करते हैं।

कांग्रेस के अध्यक्ष खड्गे ने काकी कुछ बीत चुके हैं और उनकी पीमा मोदी के लिए रागण बाला बयान काफ़ी बली मत करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हलचल पैदा करते हैं भागीरथर अय्यर। उन्होंने पीमा मोदी के लिए बहुत ही सरसी शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने तो नीच, कातिल जैसे शब्दों का खुलेआम इस्तेमाल किया था जिसमें उनकी हताशा साफ झलकती है।

कांशीरयों की तो सुकी काकी लंबी है। बांधे वह अकीर रंजन हों या विधेयक सित या सित सचर नियमन और भिंयका गंधी। सभी ने मौका देखाकर बहल हल्के शब्दों का इस्तेमाल किया जिससे उनकी खोश का पता चलता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मोदी और उनकी पार्टी ने ऐसे अपराधों शब्दों और टिप्पणियों को अपने नाम के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने करीबी सांसदों को सामने दस शब्दों और उन्हें बोलने वाले को खिलाफ गानाल बना दिया। नरेंद्र मोदी को बाप बाला कहकर उनका उपहास उड़ाने वाले विपक्षियों को तो उन्होंने अपने काफ़ी और उपस्थितियों में उल्लेख दिया दिया। आज बाप बाला शब्द महानतकाश लोगों के सम्मान का अपमान बन गया है।

शिक्षकों के सहयोग से ही समाज

संबाददाता-बहराइच। राम, कृष्ण परमहंस निहार इंटर कॉलेज भारतीय बस्तियों में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि पद्म कैंबिनेट मंत्री हनुमान सिंह व विधायक अश्विनी रवींद्र गुप्ता कलमपुरी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विद्यार्थियों के नर्तक नृत्य बच्चों ने सांस्कृतिक व रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी को नम्रुणुध कर दिया। विद्यार्थ्य प्रभकर अरुण कुमार पांडेय व जयदेवधर पीएन यादव ने अतिथियों का बेग लगाकर स्वागत किया। अतिथियों ने बच्चों की उपज्वल भविष्य की कामना करते हुए स्वामी विवेकानंद तथा परमहंस जैसे ज्ञानी बनने का उपदेश दिया। रवींद्र गुप्ता कलमपुरी ने कहा कि शिक्षक समाज

में आणा बढवाल-रवींद्र गुप्ता

में बढवाल बढाया तथा समाज और बढेगा। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने राम और अव्व कि और मनमोहक प्रस्तुति की, जिससे देखकर सभी लोग मन मुग्ध हो गए। दास गणेशा व भाग्यन शंकर कि झांकी के साथ मगत सिंह कि झांकी एवं अन्य कार्यक्रम ने लोगों को मन मग लिया। अंत में बन्दे मातरम व शहीदों की शहादत पर बच्चों ने नतम प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे मधु मिश्र, लखी शुक्ला, शुभम यादव, श्रेयांशी यादव, पुनम, सपना, अमिता, आरश्र्वा, आयुधानम, आनामिका, नन्दनी, कदरिमा, अरुणरा, सर्वजीत, संदीप, अंशु, मुदरेश, अशिका समृद्धि, सीमा रुद्राणी, नितीन आदि छात्रों ने अपनी बाने का उपदेश दिया। रवींद्र गुप्ता कलमपुरी ने कहा कि शिक्षक समाज

हक के लिए लामबंद हुए

संबाददाता-बहराइच। पुनरी पेसन बढाती समेत कई मांगों को लेकर सोमवार को बैरिफा शिक्षक लामबंद हुए। बीएसए कार्यालय परिसर में नतम देकर हक की आवाज बुलंद की। कहा कि जल्द ही उनकी सुवावाई नही हुई तो वे लोग एक अस्पताल कर देंगे। कहा कि लंबे समय से उनकी मांगों को सरकार हल स्तर पर नजरअंदाज कर रही है। जल्द ही वे नजर आंदोलन की राहत अख्तियार करेंगे। सीएम से संबंधित ज्ञानन बीएसए आतिथि शिवा को सीपा। जिला बस्ती शिक्षा अडि कार की कार्यलय में सोमवार को जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ की ओर से बैरिफा शिक्षा में किया जा रहे डिजिटलाइजेशन को विरोध में 18

शिक्षक, सुनवाई न होने पर अनइस्टॉल करेंगे ए

सुचीय मांग के लिए घरना प्रदर्शन किया। जिल्लख विद्या विलास पाठक कहा कि सरकार शिक्षकों की मांगों को अनुसुचा कर रही है। उनकी मांगों को समय रहते न माना गया तो ऑनलाइन काम अपने मोबाइल कर कर रहे हैं, वह सभी ऐप भी अनइस्टॉल कर देंगे। कहा कि सरकार साठों से वार्ता कर शिक्क समस्याओं को समाप्त करे। प्रांतीय प्रमुख संसंधक खास कृष्ण पाठक ने कहा कि समय रहते सरकार शिक्षक की मांगों को पूरा कर समस्या विहीन करे। प्रांतीय संयुक्त मंत्री भूपेंद्र श्रिवास्तव ने सरकार को सावधान शिक्षा कि शिक्षा अवर सुजन है तो वह विनाश भी करना जानता है। हम शैक्षिक कार्य करना चाहते हैं। हमें वह

बलात्कारी को आजीवन कारावास

व 50 हजार का अर्थ दंड

संबाददाता-श्रावस्ती।

बलात्कार के आरोपी का आरोप सिद्ध होने के बाद न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा मिली है। इसके साथ ही 50 हजार का अर्थदंड लगाया गया है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजय बहादुर सिंह ने बताया कि इकोनी शासक के एक गांव का है। 2011 में एक किशोरी को युवक भाग ले गया था। इससे बाद जबरन शादी कर ली। पीडिता के पिता के तत्वरूप पर भाग इकोनी में मुकदमा दंड हुआ था। पुलिस ने पीडिता को बरामद कर लिया और न्यायालय ने बयान दर्ज करवाया। पीडिता ने बताया कि उसकी शादी घटना से तीन वर्ष पहले विजय के साथ हुई थी। वह भारत लाल के

धर्म प्रचार और ठाकुर जी की सेवा

के लिए नयना बही साध्वी सुनैना

—भारतीय बस्ती संबाददाता— अयोध्या। नगवान श्री राम की प्रेमस्थली अयोध्या दत्त प्रतिदिन जन्मजुओं की आवागमन से गुलजार रहती है प्राण प्रलिष्ठा के बाद लाठी की संख्या में प्रतिदिन प्रहारी दर्शन करते हैं और इसी क्रम में सनान धर्म के प्रति लोगों की आस्था जागृत हो रही है और वह भगवान के लिए अपना जीवन समर्पित करना चाहते हैं इसी क्रम में राजस्थान में जन्मी नयना उत्तर गुजरात के पाटन में वर्षों से जो सेवा का कार्य कर रही है और अयोध्या के सिद्ध पीठ देव जी के मंदिर के पीठाधीश्वर महंत राजेंद्र दास महाराज से जुड़ी थी प्राण प्रलिष्ठा के बाद उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न हुआ और वह अयोध्या पहुंचकर श्री महाराज जी से बैरगी की दीक्षा प्राप्त की और राजेंद्र दास महाराज ने उनका वैष्णो नाम साध्वी सुनैना रखा दिया। श्री श्री 1008 महंत राजेंद्र दास महाराज ने बताया कि मगवान के प्रति कर्त्तव्य भी आसक्त हो सनान हैं और वर्तमान समय में सनान 6 र्म के बारे में लोग जानने लगे हैं इसी क्रम में गुजरात की नयना जो अयोध्या से जुड़ी थी आज से वैराग्य अपना लिया है अब वह निरंतर संत

दियागों को किया गुण

द्राई साइकिल का वितरण

संबाददाता-श्रावस्ती। एएसएबी 62वीं जालिनी निगमा में सोमवार को दियोगों के लिए द्राई साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सप्त दियोग वक्तव्यों को द्राई साइकिल प्रदान किया गया। इससे उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। दियोगों की मदद के लिए रू क्रास सोसाइटी की ओर से दियोगी योनाएं संचालित की जा रही हैं। इसी क्रम में एएसएबी कर्म निगमा में भी वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जिसमें एएसएबी कमांडर रवीन्द्र कुमार राजवंश ने सप्त दियोगों को द्राई साइकिल का वितरण किया। उन्होंने कहा कि रू क्रास की यह पहल सहायनी है। दियोगों को आने जाने के लिए दूरतों पर निर्भर होने हैं। लेकिन द्राई साइकिल प्राप्त हो जाने से उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में सहूलियत मिलेगी।

बच्चों में विकसित किया गुण तर्क करने की शक्ति-कृतिका शर्मा

संबाददाता-श्रावस्ती। बैरिफा शिक्षा विभाग की ओर से कलेक्ट्रेट में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। जिसमें प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यार्थियों के बच्चों व अपने अपने माइड प्रस्तुत करके उनके बारे में अतिथियों को समझाया। इस मोर्चे पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया।

कलेक्ट्रेट स्थित तथाराज हाल

में राष्ट्रीय अधिकार अभियान कार्यक्रम के तहत विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। जिसका जिलाधिकारी कृतिका शर्मा, जिला महामंत्री रमन सिंह और जिलाधिकारी अमरेंद्र कुमार वर्मा ने द्वाी प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। जिलाधिकारी ने कहा कि आज का युग विज्ञान का युग है, सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान है। छात्र-छात्राएं

आकांक्षी ब्लाक रुपईडीह में तीन साल में तीसरी बार हुई क्षेत्र पंचायत की बैठक

संबाददाता-गोण्डा। आकांक्षी ब्लाक में तीन साल में सोमवार को तीसरी बार हुई क्षेत्र पंचायत की बैठक मजल 42 निम्न में पंचायत हो गई। इसमें 125 ग्राम पंचायतों से आए करोड़ों के विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। हालांकि, बैठक में जन्मतु निमित्त प्यों की उपस्थिति भी बहुत कम रही। बैठक की अध्यक्षता पूर्व मंत्री विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह की अनुज वृष व लॉक बंदीता सिंह ने की। इसका संचालन बीडीओ मयूजय यादव ने किया। बीडीओ ने पिछली बैठक की पुष्टि करते हुए बनी कार्य योजनाओं के सापेक्ष अडि कतन का होने पर निराशा

मनरंगा मणिकों के मुगतान को लेकर ग्राम प्रधान कलेक्ट्रेट पहुंचे

संबाददाता-बलरामपुर। ग्राम प्रधाओं की समस्याओं को लेकर सोमवार को अडिल भारतीय पंचायत परिषद के बैनर तले सभी ब्लाकों के ग्राम प्रधाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर बीएम को ज्ञापन सीपा। ग्राम प्रधाओं ने मनरंगा मददगी का मुगतान करने खाते सहित अन्य समस्याओं का समाधान करण जनों की मांग की है। डीएम पर ग्राम प्रधाओं की समस्याओं का समाधान करने का आशवासन दिया है। अडिल भारतीय पंचायत परिषद जिलाध्यक्ष गुलजारी लाल शुक्ल व प्रदेश सचिव विजय निपाटी के नेतृत्व में सभी नौ ब्लाकों के अध्यक्ष व अन्य प्रधाओं ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर बीएम को ज्ञापन सीपा। ग्राम प्रधान ने कहा है कि बीते 11 नवंबर से मनरंगा में कार्यरत अधिकारी की मजदूरी का मुगतान नहीं किया गया है। बीएम के अनुभार 15 दिनों के भीतर मुगतान हो जाना चाहिए। नजदूरी का

बगैर नेम्रोलाजिस्ट के हो रहा किडनी के मरीजों का इलाज

संबाददाता-बहराइच। जिले में किडनी मरीजों की संख्या दिनदिनी बढ़ती जा रही है। जिले के किडनी मरीजों के इलाज के लिए संयुक्त जिला चिकित्सालय में डाइयलिसिस गुना संचालन किया जा रहा है। बगैर नेम्रोलाजिस्ट की तैनाती के यहां किडनी मरीजों की डाइयलिसिस हो रही है। स्थिति यह है कि कोलकाता के एक डाक्टर गंभीर किडनी मरीजों को ऑनलाइन परामर्श देते हैं, जिसके बाद उनका इलाज किया जाता है। गंभीर मरीजों को लखनऊ या आसपास के जिलों में भेजा जाता है। जिलाधिकारी ने कहा कि सोमवार को नेम्रोलाजिस्ट की तैनाती के लिए शासन को पत्र भेजा गया है। डीएम ने गुर्दा रोग को लखनऊ के शीघ्र ही तैनाती का विचारित किया।

संयुक्त जिला चिकित्सालय में किडनी के मरीजों के लिए डाइयलिसिस यूनित की स्थापना कई वर्ष पहले की गई थी। यूनित की स्थापना तो जरूर कर दी गई लेकिन विशेषज्ञ एवं अन्य स्टेफ की तैनाती नहीं की गई। आज भी अस्पताल के डाइयलिसिस यूनित में बगैर नेम्रोलाजिस्ट के ही मरीजों का इलाज किया जा रहा है। किडनी ट्रांसप्लांट के मरीजों को पीजीआई लखनऊ, गोरखपुर व दिल्ली तक का चक्कर लगाना पड़ता है। विशेषज्ञों की मांगें तो शरीर में एक ही सफाई करने वाले अंग रीक से काम न करने पर मरीज के घात में गंदगी फैल जाती है। इसकी सफाई कराने के लिए उसे डाइयलिसिस करना पड़ता है। संयुक्त जिला अस्पताल के डाइयलिसिस यूनित में मौजूद

हम शपथ लेते हैं कि निर्भीक होकर मतदान करेंगे- डीएम

संबाददाता-श्रावस्ती। लोक सभा चुनाव में मतदान प्रक्रिया बढ़ाने के लिए गांव गांव चौपाल लॉन्चिंग जा रही है। जिसमें आम मतदाताओं को मतदान करने की शपथ दिलाई जा रही है। सोमवार को जन्मतुता के प्राथमिक स्कूल बरगडीह में चौपाल लगा कर लोगों को मतदान के लाभ बताए और शपथ दिलाई गई। जिला निर्वाचन अधिकारी कृतिका शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरस्या की अध्यक्षता में मतदाता जागरूकता चौपाल का आयोजन प्राथमिक स्कूल बरगडीह में किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने गांव की महिलाओं, आंगनवाडी कार्यकर्ताओं एवं ग्राम पंचायत से सीता बतवर्धनी एवं ग्राम दौरान सभी को मतदान करने तथा दूरतों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया। जिलाधिकारी ने लोगों को मतदाता शपथ दिलाई कि हम भारत के निर्वाचन कोसले में अपनी आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं

85 वर्ष से ऊपर वाले मतदाताओं को मिलेगी पोस्टल बैलेट की सुविधा

संबाददाता-बलरामपुर। 85 वर्ष की आयु से ऊपर वाले मतदाताओं को मतदान करने के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा प्राप्त कराई गई है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 85 वर्ष की आयु से ऊपर के मतदाताओं को रेंबर किया जाता है। हर मास शिविर का आयोजन करने की भी योजना बनाई गई है। किडनी ट्रांसप्लांट के मरीजों को पीजीआई लखनऊ रेफर कर दिया जाता है। विशेषज्ञों की मांगें तो गुर्दा की बीमारी का एक सामान्य लक्षण गुरुभूतता में थकावट का होना होता है। जैसे-जैसे गुर्दा की खराबी बढ़ती जाती है वह लक्षण स्पष्ट होता जाता है। सामान्य जनों की तुलना में यह व्यक्ति अधिक थका हुआ महसूस करता है। ज्यादा गतिविधियों को करने में वह असमर्थ होते हैं। ऐसा काफी हद तक रक्त में विषाक्त पदार्थों और अशुद्धियों के संचयन के कारण होता है, जिसके परिणामस्वरूप रक्त खराब हो जाते हैं। इसके अलावा रक्त में कनी, सुबह उठती आना, पैनीयता, पेशाब की आगुति में परिवर्तन, मूत्र से खून या रक्त का आना, सूखी त्वचा में झगुगी होना, पीठ या पेट के निचले हिस्से में दर्द होना के साथ-साथ किडनी के बीमारी का प्रमुख लक्षण है। अरविंद सिंह, जिलाधिकारी ने कहा कि नेम्रोलाजिस्ट की तैनाती के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जा रहा है। डाइयलिसिस की यूनित यहां के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस यूनित का संचालन लख दंग से हो सके, इसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। अस्पताल प्रशासन के साथ-साथ यूनित की व्यवस्थाओं को सुचारुने के लिए लायकारा कोशिशें की जा रही हैं। सोमवार को शासन को अनुमत्यारक पत्र भेजा गया है। उम्मीय है कि जल्द ही किडनी के मरीज जिले में मिल चुके हैं। जो गंभीर मरीज होते हैं उन्हें लखनऊ व अन्य जिलों में

संबाददाता-श्रावस्ती।

संयुक्त जिला चिकित्सालय में किडनी के मरीजों के लिए डाइयलिसिस यूनित की स्थापना कई वर्ष पहले की गई थी। यूनित की स्थापना तो जरूर कर दी गई लेकिन विशेषज्ञ एवं अन्य स्टेफ की तैनाती नहीं की गई। आज भी अस्पताल के डाइयलिसिस यूनित में बगैर नेम्रोलाजिस्ट के ही मरीजों का इलाज किया जा रहा है। किडनी ट्रांसप्लांट के मरीजों को पीजीआई लखनऊ, गोरखपुर व दिल्ली तक का चक्कर लगाना पड़ता है। विशेषज्ञों की मांगें तो शरीर में एक ही सफाई करने वाले अंग रीक से काम न करने पर मरीज के घात में गंदगी फैल जाती है। इसकी सफाई कराने के लिए उसे डाइयलिसिस करना पड़ता है। संयुक्त जिला अस्पताल के डाइयलिसिस यूनित में मौजूद

संबाददाता-श्रावस्ती।

संयुक्त जिला चिकित्सालय में किडनी के मरीजों के लिए डाइयलिसिस यूनित की स्थापना कई वर्ष पहले की गई थी। यूनित की स्थापना तो जरूर कर दी गई लेकिन विशेषज्ञ एवं अन्य स्टेफ की तैनाती नहीं की गई। आज भी अस्पताल के डाइयलिसिस यूनित में बगैर नेम्रोलाजिस्ट के ही मरीजों का इलाज किया जा रहा है। किडनी ट्रांसप्लांट के मरीजों को पीजीआई लखनऊ, गोरखपुर व दिल्ली तक का चक्कर लगाना पड़ता है। विशेषज्ञों की मांगें तो शरीर में एक ही सफाई करने वाले अंग रीक से काम न करने पर मरीज के घात में गंदगी फैल जाती है। इसकी सफाई कराने के लिए उसे डाइयलिसिस करना पड़ता है। संयुक्त जिला अस्पताल के डाइयलिसिस यूनित में मौजूद

संबाददाता-श्रावस्ती।

संयुक्त जिला चिकित्सालय में किडनी के मरीजों के लिए डाइयलिसिस यूनित की स्थापना कई वर्ष पहले की गई थी। यूनित की स्थापना तो जरूर कर दी गई लेकिन विशेषज्ञ एवं अन्य स्टेफ की तैनाती नहीं की गई। आज भी अस्पताल के डाइयलिसिस यूनित में बगैर नेम्रोलाजिस्ट के ही मरीजों का इलाज किया जा रहा है। किडनी ट्रांसप्लांट के मरीजों को पीजीआई लखनऊ, गोरखपुर व दिल्ली तक का चक्कर लगाना पड़ता है। विशेषज्ञों की मांगें तो शरीर में एक ही सफाई करने वाले अंग रीक से काम न करने पर मरीज के घात में गंदगी फैल जाती है। इसकी सफाई कराने के लिए उसे डाइयलिसिस करना पड़ता है। संयुक्त जिला अस्पताल के डाइयलिसिस यूनित में मौजूद

संबाददाता-श्रावस्ती।

संयुक्त जिला चिकित्सालय में किडनी के मरीजों के लिए डाइयलिसिस यूनित की स्थापना कई वर्ष पहले की गई थी। यूनित की स्थापना तो जरूर कर दी गई लेकिन विशेषज्ञ एवं अन्य स्टेफ की तैनाती नहीं की गई। आज भी अस्पताल के डाइयलिसिस यूनित में बगैर नेम्रोलाजिस्ट के ही मरीजों का इलाज किया जा रहा है। किडनी ट्रांसप्लांट के मरीजों को पीजीआई लखनऊ, गोरखपुर व दिल्ली तक का चक्कर लगाना पड़ता है। विशेषज्ञों की मांगें तो शरीर में एक ही सफाई करने वाले अंग रीक से काम न करने पर मरीज के घात में गंदगी फैल जाती है। इसकी सफाई कराने के लिए उसे डाइयलिसिस करना पड़ता है। संयुक्त जिला अस्पताल के डाइयलिसिस यूनित में मौजूद

संबाददाता-श्रावस्ती।

संयुक्त जिला चिकित्सालय में किडनी के मरीजों के लिए डाइयलिसिस यूनित की स्थापना कई वर्ष पहले की गई थी। यूनित की स्थापना तो जरूर कर दी गई लेकिन विशेषज्ञ एवं अन्य स्टेफ की तैनाती नहीं की गई। आज भी अस्पताल के डाइयलिसिस यूनित में बगैर नेम्रोलाजिस्ट के ही मरीजों का इलाज किया जा रहा है। किडनी ट्रांसप्लांट के मरीजों को पीजीआई लखनऊ, गोरखपुर व दिल्ली तक का चक्कर लगाना पड़ता है। विशेषज्ञों की मांगें तो शरीर में एक ही सफाई करने वाले अंग रीक से काम न करने पर मरीज के घात में गंदगी फैल जाती है। इसकी सफाई कराने के लिए उसे डाइयलिसिस करना पड़ता है। संयुक्त जिला अस्पताल के डाइयलिसिस यूनित में मौजूद

संबाददाता-श्रावस्ती।

संयुक्त जिला चिकित्सालय में किडनी के मरीजों के लिए डाइयलिसिस यूनित की स्थापना कई वर्ष पहले की गई थी। यूनित की स्थापना तो जरूर कर दी गई लेकिन विशेषज्ञ एवं अन्य स्टेफ की तैनाती नहीं की गई। आज भी अस्पताल के डाइयलिसिस यूनित में बगैर नेम्रोलाजिस्ट के ही मरीजों का इलाज किया जा रहा है। किडनी ट्रांसप्लांट के मरीजों को पीजीआई लखनऊ, गोरखपुर व दिल्ली तक का चक्कर लगाना पड़ता है। विशेषज्ञों की मांगें तो शरीर में एक ही सफाई करने वाले अंग रीक से काम न करने पर मरीज के घात में गंदगी फैल जाती है। इसकी सफाई कराने के लिए उसे डाइयलिसिस करना पड़ता है। संयुक्त जिला अस्पताल के डाइयलिसिस यूनित में मौजूद

संबाददाता-श्रावस्ती।

संयुक्त जिला चिकित्सालय में किडनी के मरीजों के लिए डाइयलिसिस यूनित की स्थापना कई वर्ष पहले की गई थी। यूनित की स्थापना तो जरूर कर दी गई लेकिन विशेषज्ञ एवं अन्य स्टेफ की तैनाती नहीं की गई। आज भी अस्पताल के डाइयलिसिस यूनित में बगैर नेम्रोलाजिस्ट के ही मरीजों का इलाज किया जा रहा है। किडनी ट्रांसप्लांट के मरीजों को पीजीआई लखनऊ, गोरखपुर व दिल्ली तक का चक्कर लगाना पड़ता है। विशेषज्ञों की मांगें तो शरीर में एक ही सफाई करने वाले अंग रीक से काम न करने पर मरीज के घात में गंदगी फैल जाती है। इसकी सफाई कराने के लिए उसे डाइयलिसिस करना पड़ता है। संयुक्त जिला अस्पताल के डाइयलिसिस यूनित में मौजूद

संबाददाता-श्रावस्ती।

संयुक्त जिला चिकित्सालय में किडनी के मरीजों के लिए डाइयलिसिस यूनित की स्थापना कई वर्ष पहले की गई थी। यूनित की स्थापना तो जरूर कर दी गई लेकिन विशेषज्ञ एवं अन्य स्टेफ की तैनाती नहीं की गई। आज भी अस्पताल के डाइयलिसिस यूनित में बगैर नेम्रोलाजिस्ट के ही मरीजों का इलाज किया जा रहा है। किडनी ट्रांसप्लांट के मरीजों को पीजीआई लखनऊ, गोरखपुर व दिल्ली तक का चक्कर लगाना पड़ता है। विशेषज्ञों की मांगें तो शरीर में एक ही सफाई करने वाले अंग रीक से काम न करने पर मरीज के घात में गंदगी फैल जाती है। इसकी सफाई कराने के लिए उसे डाइयलिसिस करना पड़ता है। संयुक्त जिला अस्पताल के डाइयलिसिस यूनित में मौजूद

संबाददाता-श्रावस्ती।

संयुक्त जिला चिकित्सालय में किडनी के मरीजों के लिए डाइयलिसिस यूनित की स्थापना कई वर्ष पहले की गई थी। यूनित की स्थापना तो जरूर कर दी गई लेकिन विशेषज्ञ एवं अन्य स्टेफ की तैनाती नहीं की गई। आज भी अस्पताल के डाइयलिसिस यूनित में बगैर नेम्रोलाजिस्ट के ही मरीजों का इलाज किया जा रहा है। किडनी ट्रांसप्लांट के मरीजों को पीजीआई लखनऊ, गोरखपुर व दिल्ली तक का चक्कर लगाना पड़ता है। विशेषज्ञों की मांगें तो शरीर में एक ही सफाई करने वाले अंग रीक से काम न करने पर मरीज के घात में गंदगी फैल जाती है। इसकी सफाई कराने के लिए उसे डाइयलिसिस करना पड़ता है। संयुक्त जिला अस्पताल के डाइयलिसिस यूनित में मौजूद

संबाददाता-श्रावस्ती।

संयुक्त जिला चिकित्सालय में किडनी के मरीजों के लिए डाइयलिसिस यूनित की स्थापना कई वर्ष पहले की गई थी। यूनित की स्थापना तो जरूर कर दी गई लेकिन विशेषज्ञ एवं अन्य स्टेफ की तैनाती नहीं की गई। आज भी अस्पताल के डाइयलिसिस यूनित में बगैर नेम्रोलाजिस्ट के ही मरीजों का इलाज किया जा रहा है। किडनी ट्रांसप्लांट के मरीजों को पीजीआई लखनऊ, गोरखपुर व दिल्ली तक का चक्कर लगाना पड़ता है। विशेषज्ञों की मांगें तो शरीर में एक ही सफाई करने वाले अंग रीक से काम न करने पर मरीज के घात में गंदगी फैल जाती है। इसकी सफाई कराने के लिए उसे डाइयलिसिस करना पड़ता है। संयुक्त जिला अस्पताल के डाइयलिसिस यूनित में मौजूद

संबाददाता-श्रावस्ती।

संयुक्त जिला चिकित्सालय में किडनी के मरीजों के लिए डाइयलिसिस यूनित की स्थापना कई वर्ष पहले की गई थी। यूनित की स्थापना तो जरूर कर दी गई लेकिन विशेषज्ञ एवं अन्य स्टेफ की तैनाती नहीं की गई। आज भी अस्पताल के डाइयलिसिस यूनित में बगैर नेम्रोलाजिस्ट के ही मरीजों का इलाज किया जा रहा है। किडनी ट्रांसप्लांट के मरीजों को पीजीआई लखनऊ, गोरखपुर व दिल्ली तक का चक्कर लगाना पड़ता है। विशेषज्ञों की मांगें तो शरीर में एक ही सफाई करने वाले अंग रीक से काम न करने पर मरीज के घात में गंदगी फैल जाती है। इसकी सफाई कराने के लिए उसे डाइयलिसिस करना पड़ता है। संयुक्त जिला अस्पताल के डाइयलिसिस यूनित में मौजूद

संबाददाता-श्रावस्ती।

संयुक्त जिला चिकित्सालय में किडनी के मरीजों के लिए डाइयलिसिस यूनित की स्थापना कई वर्ष पहले की गई थी। यूनित की स्थापना तो जरूर कर दी गई लेकिन विशेषज्ञ एवं अन्य स्टेफ की तैनाती नहीं की गई। आज भी अस्पताल के डाइयलिसिस यूनित में बगैर नेम्रोलाजिस्ट के ही मरीजों का इलाज किया जा रहा है। किडनी ट्रांसप्लांट के मरीजों को पीजीआई लखनऊ, गोरखपुर व दिल्ली तक का चक्कर लगाना पड़ता है। विशेषज्ञों की मांगें तो शरीर में एक ही सफाई करने वाले अंग रीक से काम न करने पर मरीज के घात में गंदगी फैल जाती है। इसकी सफाई कराने के लिए उसे डाइयलिसिस करना पड़ता है। संयुक्त जिला अस्पताल के डाइयलिसिस यूनित में मौजूद

संबाददाता-श्रावस्ती।

संयुक्त जिला चिकित्सालय में किडनी के मरीजों के लिए डाइयलिसिस यूनित की स्थापना कई वर्ष पहले की गई थी। यूनित की स्थापना तो जरूर कर दी गई लेकिन विशेषज्ञ एवं अन्य स्टेफ की तैनाती नहीं की गई। आज भी अस्पताल के डाइयलिसिस यूनित में बगैर नेम्रोलाजिस्ट के ही मरीजों का इलाज किया जा रहा है। किडनी ट्रांसप्लांट के मरीजों को पीजीआई लखनऊ, गोरखपुर व दिल्ली तक का चक्कर लगाना पड़ता है। विशेषज्ञों की मांगें तो शरीर में एक ही सफाई करने वाले अंग रीक से काम न करने पर मरीज के घात में गंदगी फैल जाती है। इसकी सफाई कराने के लिए उसे डाइयलिसिस करना पड़ता है। संयुक्त जिला अस्पताल के डाइयलिसिस यूनित में मौजूद

संबाददाता-श्रावस्ती।

संयुक्त जिला चिकित्सालय में किडनी के मरीजों के लिए डाइयलिसिस यूनित की स्थापना कई वर्ष पहले की गई थी। यूनित की स्थापना तो जरूर कर दी गई लेकिन विशेषज्ञ एवं अन्य स्टेफ की तैनाती नहीं की गई। आज भी अस्पताल के डाइयलिसिस यूनित में बगैर नेम्रोलाजिस्ट के ही मरीजों का इलाज किया जा रहा है। किडनी ट्रांसप्लांट के मरीजों को पीजीआई लखनऊ, गोरखपुर व दिल्ली तक का चक्कर लगाना पड़ता है। विशेषज्ञों की मांगें तो शरीर में एक ही सफाई करने वाले अंग रीक से काम न करने पर मरीज के घात में गंदगी फैल जाती है। इसकी सफाई कराने के लिए उसे डाइयलिसिस करना पड़ता है। संयुक्त जिला अस्पताल के डाइयलिसिस यूनित में मौजूद

संबाददाता-श्रावस्ती।

संयुक्त जिला चिकित्सालय में किडनी के मरीजों के लिए डाइयलिसिस यूनित की स्थापना कई वर्ष पहले की गई थी। यूनित की स्थापना तो जरूर कर दी गई लेकिन विशेषज्ञ एवं अन्य स्टेफ की तैनाती नहीं की गई। आज भी अस्पताल के डाइयलिसिस यूनित में बगैर नेम्रोलाजिस्ट के ही मरीजों का इलाज किया जा रहा है। किडनी ट्रांसप्लांट के मरीजों को पीजीआई लखनऊ, गोरखपुर व दिल्ली तक का चक्कर लगाना पड़ता है। विशेषज्ञों की मांगें तो शरीर में एक ही सफाई करने वाले अंग रीक से काम न करने पर मरीज के घात में गंदगी फैल जाती है। इसकी सफाई कराने के लिए उसे डाइयलिसिस करना पड़ता है। संयुक्त जिला अस्पताल के डाइयलिसिस यूनित में मौजूद

संबाददाता-श्रावस्ती।

संयुक्त जिला चिकित्सालय में किडनी के मरीजों के लिए डाइयलिसिस यूनित की स्थापना कई वर्ष पहले की गई थी। यूनित की स्थापना तो जरूर कर दी गई लेकिन विशेषज्ञ एवं अन्य स्टेफ की तैनाती नहीं की गई। आज भी अस्पताल के डाइयलिसिस यूनित में बगैर नेम्रोलाजिस्ट के ही मरीजों का इलाज किया जा रहा है। किडनी ट्रांसप्लांट के मरीजों को पीजीआई लखनऊ, गोरखपुर व दिल्ली तक का चक्कर लगाना पड़ता है। विशेषज्ञों की मांगें तो शरीर में एक ही सफाई करने वाले अंग रीक से काम न करने पर मरीज के घात में गंदगी फैल जाती है। इसकी सफाई कराने के लिए उसे डाइयलिसिस करना पड़ता है। संयुक्त जिला अस्पताल के डाइयलिसिस यूनित में मौजूद

